31दिसंबर, 1997 को दर्ज की थी और सभी उद्घोषकों के लिए नहीं।विद्वान न्यायाधीशों ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 3 सितंबर, 1998 को जारी एक परिपत्र का भी संदर्भ दिया है, जिसमें कहा गया है कि कर को 90 दिनों की समाप्ति के बाद भी स्वीकार किया जा सकता है और इसलिए, यह अनुमान लगाया गया है कि आयुक्त के पास देरी को माफ करने की शक्ति थी।इस परिपत्र में अन्य बातों के अलावा कहा गया है कि ब्याज की गणना करने की अवधि घोषणा की तारीख से 90 दिन होगी और यदि 90वां दिन बैंक अवकाश होता है, तो 91वें दिन अगले कार्य दिवस के रूप में भुगतान वैध होगा।बोर्ड ने, हमारी राय में, स्पष्ट रूप से कहा है, लेकिन परिपत्र में यह खंड किसी भी तरह से आयुक्त को घोषणा स्वीकार करने की शक्ति नहीं देता है, जहां घोषणा की तारीख से 90 दिनों की अवधि के बाद कर जमा किया जाता है।सामान्य तौर पर, हम इस मामले को निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ के पास भेज देते, लेकिन इस पाठ्यक्रम को अपनाना आवश्यक नहीं है क्योंकि लक्ष्मी मित्तल के मामले *(ऊपर)* में निर्धारित अनुपात के आधार पर भी हमारे सामने याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं होगा।लक्ष्मी मित्तल के मामले (ऊपर) में याचिकाकर्ता ने तीन महीने के भीतर जमा करने में विफलता के लिए स्पष्टीकरण दिया था क्योंकि वह एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी और उस स्पष्टीकरण को पीठ ने स्वीकार कर लिया था।हमारे समक्ष मामले में, याचिकाकर्ता ने आयुक्त के समक्ष कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जब उनका प्रतिनिधि 6 मई, 1998 और 12 मई, 1998 को आयुक्त के समक्ष पेश हुआ और देरी की माफी मांगी क्योंकि यह केवल एक दिन की थी।यह देरी क्यों हुई, यह नहीं बताया गया।इसलिए, भले ही हम लक्ष्मी मित्तल के मामले (ऊपर) में उक्ति का पालन करते हैं, याचिकाकर्ता द्वारा दायर घोषणा को देरी के लिए किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में खारिज कर दिया जाना था।इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता ने अपनी रिट याचिका पर कुछ स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।इस प्रकार आक्षेपित क्रम में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

(4) परिणाम में, रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे ख़ारिज किया जाता है।कॉस्ट के बारे में कोई आदेश नहीं है।

आरएनआर

न्यायमूर्तिगण जवाहर लाल गुप्ता और वी. एम. जैन के समक्ष

डॉ. रदानंदन जीवन डैश,-पिटिशनरवर्सस

डॉ. एन. के. गांगुली और एक और-उत्तरदाता

1999 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 16547

20दिसंबर, 1999

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, नियम, *1967*-नियम *7*-नियम 7 *(4)* प्रावधानित करता है कि करता है।

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, नियम, *1967*-आर. एल. *7*-नियम 7 *(4)*

संस्थान के कार्यवाहक निदेशक की सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर या *'किसी अन्य व्यक्ति'*, जिसके लिए कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाने हैं कि नियुक्ति प्रावधानित करता है-एक सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर की अनदेखी की गई है और संस्थान निकाय ने ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण देते हुए दूसरे को कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है-इसे चुनौती दी-क्या ऐसी नियुक्ति अवैध है और नियम *7* की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है-यथास्थिति वारंट जारी करके बेदखल नहीं किया जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया कि 1967 के नियमों के नियम 7 के खंड (4) में प्रावधान है कि राष्ट्रपति "छह महीने से अधिक की अवधि के लिए निदेशक के कार्यों को देखने के लिए सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर को नियुक्त कर सकते हैं।"यह भी प्रावधान किया गया है कि "संस्थान लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए किसी अन्य व्यक्ति को छह महीने से अधिक की अवधि के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकता है।"-इस प्रकार, सामान्य नियम यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर की नियुक्ति करेगा।हालांकि, संस्थान जो एक बड़ा निकाय है, उसे किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है।यह अच्छे कारणों से ऐसा कर सकता है जिन्हें लिखित रूप में दर्ज करना पड़ता है।

(पैरा 11)

अभिनिर्धारित किया कि प्रोफेसर एन. के. गांगुली कार्यवाहक निदेशक के पद पर कब्जा करने वाले नहीं हैं।उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया है।उनकी नियुक्ति नियम 7 के अनुरूप है।इसलिए, वह रिट ऑफ क्वो-वारंटो जारी करके निष्कासित किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

(पैरा 28)

आर. एस. मित्तल, वरिष्ठ अधिवक्ता और अधिवक्तासुश्री पालिका मोंगा, याचिकाकर्ता की ओर से

वरिष्ठ अधिवक्ता डी. एस. नेहरा अधिवक्ता मुनीश भारद्वाज के साथ प्रतिवादीगणओं की ओर से ।

निर्णय

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता *(O)*

(1) क्या प्रोफेसर एन.के.गांगुली, पद निदेशक, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के पद पर कब्ज़ा किया है? क्या प्रोफेसर गांगुली को रिट ऑफ क्वो-वारंटो जारी करके पद से हटा दिया जाए? यह दो छोटे प्रश्न हैं जो इस रिट याचिका में विचार के लिए उठते हैं।

(2) कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है।

(3) याचिकाकर्ता संस्थान में एंडोक्राइनोलॉजी के प्रोफेसर हैं।वे संस्थान में सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर हैं।यह जानने पर प्रो.एन. के. गांगुली, जो शुरू में संस्थान में सूक्ष्म जीव विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए कहा गया था, उन्होंने यथास्थिति वारंट जारी करने के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया था।यह आरोप लगाया गया था कि नियुक्ति पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ नियम, 1967 (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 7 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।

(4) याचिका को सुनवाई के लिए 30 नवंबर, 1999 को रखा गया था।पीठ ने प्रतिवादीगण को 6 दिसंबर, 1999 के लिए प्रस्ताव का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था।यह आगे निर्देश दिया गया कि "तब तक, प्रतिवादी संख्या 1 स्नातकोत्तर संस्थान के निदेशक के रूप में पदभार नहीं संभालेगा" 1 दिसंबर, 1999 को निर्देश जारी करने के लिए दो आवेदन दायर किए गए थे।प्रतिवादीगण की ओर से निवेदन किया गया कि चूंकि डॉ. गांगुली पहले ही कार्यभार संभाल चुके हैं, इसलिए स्थगन आदेश को हटा दिया जाए।याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया था कि प्रतिवादी को अंतरिम निर्देश का पालन करना चाहिए।पीठ ने इन आवेदनों का उसी दिन निपटारा कर दिया।इसके बाद, 1999 का सी.एम. संख्या 29097 दायर किया गया था।यह अभिलिखित किया गया कि संस्थान निकाय की बैठक 8 दिसंबर, 1999 को हुई थी।प्रोफेसर एन. के. गांगुली को "संस्थान के कार्यवाहक निदेशक के रूप में" नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था। इस आधार पर, यह प्रार्थना की गई कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को निदेशक के रूप में पदभार संभालने से रोकने वाले न्यायालय द्वारा पारित निषेधात्मक आदेश को निरस्त कर दिया जाए।इस आवेदन पर पीठ ने 13 दिसंबर, 1999 के आदेश के माध्यम से निर्णय लिया था।अंतरिम आदेशों को निरस्त कर दिया गया।

(5) याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त आधार उठाने की अनुमति और 8 दिसंबर, 1999 को संस्थान द्वारा लिए गए निर्णय को चुनौती देने के लिए 1999 का सी. एम. संख्या 29242 दायर किया था।इस आवेदन की सूचना प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को दी गई थी।आज, मुख्य रिट याचिका के साथ-साथ गलत भी है।आवेदन को सुनवाई के लिए रखा गया है।

(6) प्रतिवादीगण की ओर से प्रोफेसर एन.के.गांगुली ने एक संक्षिप्त जवाब दायर किया।

(7) याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री आर. एस. मित्तल ने तर्क दिया है कि नियम 7 के तहत सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर को कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।संस्थान केवल अच्छे और प्रासंगिक कारणों से ही प्रस्थान कर सकता है।वर्तमान मामले में, संस्थान द्वारा दिए गए कारण पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 1 की नियुक्ति दूषित है।अतः वे तर्क देते हैं कि प्रो.गांगुली एक हड़पने वाला है और प्रार्थना करता है कि उसे एयूओ वारंट जारी करके कार्यवाहक निदेशक के पद से हटा दिया जाए।

(8) याचिकाकर्ता की ओर से किए गए दावे का प्रतिवाद प्रतिवादीगण के वकील श्री डी. एस. नेहरा ने किया है।

(9) सबसे पहले तथ्यात्मक पहलू।यह स्वीकृत स्थिति है कि शुरू में, प्रो.गांगुली को केंद्र सरकार द्वारा निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था।8 दिसंबर, 1999 को हुई बैठक में ही संस्थान निकाय की बैठक हुई थी और प्रो.गांगुली।

इस प्रकार, जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या प्रो.एन. के. गांगुली नियम 7 की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं?

(10) नियम के प्रासंगिक भाग को निकाला जा सकता है।यह निम्न लिखितानुसार हैः—

"पदों का सृजन और नियुक्तियाँः—

xx xx xx

(3) निदेशक के पद पर नियुक्ति केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से संस्थान द्वारा की जाएगी।

(4) निदेशक के छुट्टी पर जाने या इस्तीफा देने, सेवानिवृत्त होने या पद अन्यथा खाली होने की स्थिति में, जब तक कि एक नया निदेशक नियुक्त नहीं किया जाता है, राष्ट्रपति छह महीने से अधिक की अवधि के लिए निदेशक के कार्यों को देखने के लिए सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर की नियुक्ति कर सकता हैः

बशर्ते कि संस्थान लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से किसी अन्य व्यक्ति को छह महीने से अधिक की अवधि के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकता हैः

बशर्ते कि यदि ऐसी नियुक्ति की अवधि छह महीने से अधिक होने की संभावना है, तो ऐसी नियुक्ति का विस्तार छह महीने से अधिक करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा।

(11) उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से पाया जाता है कि निदेशक के पद पर नियमित नियुक्ति संस्थान द्वारा केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ की जानी है।जहाँ तक अल्पकालिक रिक्ति का संबंध है, प्रावधान खंड (4) में निहित है।यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति "छह महीने से अधिक की अवधि के लिए निदेशक के कार्यों को देखने के लिए सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर को नियुक्त कर सकते हैं।"यह भी प्रावधान किया गया है कि "संस्थान लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए किसी अन्य व्यक्ति को छह महीने से अधिक की अवधि के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकता है।"इस प्रकार, सामान्य नियम यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर की नियुक्ति करेगा।हालांकि, संस्थान जो एक बड़ा निकाय है, उसे किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया

है।यह अच्छे कारणों से ऐसा कर सकता है जिन्हें लिखित रूप में दर्ज करना पड़ता है।

(12) उपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि संस्थान निकाय निदेशक के पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम है।यह नियुक्ति छह महीने से अधिक अवधि के लिए नहीं की जा सकती है।यदि 'संस्थान' सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर को नजरअंदाज करने का फैसला करता है, तो उसे कारण बताना होगा।

(13) वर्तमान मामले में संस्थान का क्या निर्णय है? यह मार्क 'ए' में संस्थान की कार्यवाही में सन्निहित है।वस्तु संख्या 3
यह नीचे लिखा हैः—

"प्रो. बी. के. शर्मा की निदेशक, पीजीआई के रूप में सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप कार्यवाहक निदेशक, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ की नियुक्ति।

संस्थान निकाय ने पाया कि संस्थान के कामकाज को लेकर पिछले कुछ समय से काफी विवाद रहा है।विवाद के और बढ़ने से बचने के लिए, विस्तृत चर्चा के बाद, यह महसूस किया गया कि एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के समग्र हित में, एक कार्यवाहक निदेशक की नियुक्ति करना उचित होगा जो संस्थान के हाल के कामकाज से जुड़ा नहीं है।इस संदर्भ में, संस्थान निकाय ने महसूस किया कि कार्यवाहक निदेशक के रूप में चुने गए व्यक्ति को उच्च कद का एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक होना चाहिए जो निदेशक पद के लिए उम्मीदवार नहीं है, और वर्तमान में संस्थान में काम भी नहीं कर रहा है।इन कारणों से संस्थान निकाय ने डॉ. आर. जे. दास को कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त करना उचित नहीं समझा।कार्यवाहक निदेशक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, संस्थान निकाय ने निर्णय लिया कि डॉ. एन. के. गांगुली, महानिदेशक, आई. सी. एम. आर. को कार्यवाहक निदेशक, पी. जी. आई. एम. ई. आर. के रूप में नियुक्त किया जाए, पी. जी. आई. एम. ई. आर. नियमों के नियम 7 (4) के प्रावधान के तहत अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा, एक नियमित निदेशक की नियुक्ति होने तक, या 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए, जो भी पहले हो।

संस्थान निकाय ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि विशेष चयन समिति को पीजीआईएमईआर के नियमित निदेशक के चयन में तेजी लानी चाहिए।

(14) उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान निकाय ने कार्यवाहक निदेशक की नियुक्ति के मामले पर विचार किया था।यह विचार था कि व्यक्ति को "उच्च कद का एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक" होना चाहिए।यह भी निर्णय लिया गया कि नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति "निदेशक पद का उम्मीदवार" नहीं होना चाहिए।इसके अलावा, यह भी महसूस किया गया कि उन्हें "वर्तमान में संस्थान में काम नहीं करना चाहिए"।

(15) आदेश पर विचार करने पर, हम महसूस करते हैं कि संस्थान ने दावेदारों को बाहर करना और विवाद को समाप्त करना उचित समझा था।यह कारण, हमारे विचार में, नियम 7 की आवश्यकताओं के लिए अप्रासंगिक या बाहरी नहीं था।

(16) श्री मित्तल ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि संस्थान हमेशा सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त करता रहा है।वर्तमान मामले में विचलन चयन समिति और अन्य लोगों को गलत संकेत भेजेगा।वह आगे प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता को बाहर करने का कोई कारण नहीं दिया गया है।

(17) संस्थान के निर्णय के अवलोकन पर, ऐसा प्रतीत होता है कि निदेशक के पद के लिए सभी दावेदारों को कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार से बाहर रखा गया है।इससे किसी भी उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में संकेत भेजे जाने की संभावना समाप्त हो जाती है।इसके अलावा, जिस व्यक्ति को अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है, वह आवेदक नहीं है।इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त की गई आशंका पूरी तरह से निराधार है।

(18) अन्यथा भी, यदि याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो खंड (4) का परंतुक जो संस्थान को "किसी अन्य व्यक्ति" को नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है, पूरी तरह से निरर्थक हो जाएगा।यह नियम 7 का उद्देश्य नहीं है कि केवल सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर की नियुक्ति की जाए।राष्ट्रपति को निस्संदेह यह शक्ति दी गई है।हालांकि, नियम संस्थान को किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की अनुमति देता है।एकमात्र प्रतिबंध यह है कि कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए।यह, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, वर्तमान मामले में किया गया है।

(19) श्री मित्तल ने तर्क दिया है कि प्रो.गांगुली बाहरी व्यक्ति नहीं हैं।प्रोफेसर के पद पर उनका ग्रहणाधिकार है।उनका कार्यालय पीजीआई में है। उनकी देखरेख में चार शोध विद्वान काम कर रहे हैं।इस प्रकार, संस्थान द्वारा यह दृष्टिकोण कि वह किसी बाहरी व्यक्ति की नियुक्ति कर रहा था, तथ्यात्मक रूप से मान्य नहीं है।

(20) स्वीकृत तौर पर, प्रो.गांगुली पिछले कुछ वर्षों से नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में काम कर रहे हैं।वह काफी समय से पीजीआई से प्रतिनियुक्ति पर हैं।वह निदेशक पद के लिए भी आवेदक नहीं हैं।इस स्थिति में, यह सच है कि वह संस्थान के लिए बिल्कुल अजनबी नहीं है।उन्हें संकाय और संस्थान के कामकाज के बारे में अच्छी जानकारी है।साथ ही, वह निदेशक के पद के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं।इस प्रकार, संस्थान द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को पूरी तरह से अवैध या अप्रासंगिक विचारों पर आधारित नहीं कहा जा सकता है।

(21) क्या परित्यक्त तथ्यात्मक स्थिति के बावजूद रिट ऑफ़ क्वो वारंटो जारी किया जाना चाहिए? श्री मित्तल ने यह तर्क देने के लिए विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है कि जब भी नियुक्ति कानून के अनुरूप नहीं होती है, तो न्यायाल्य रिट ऑफ़ क्वो वारंटो जारी करके पदधारी को बाहर कर देती है। अधिवक्ता द्वारा लॉर्डशिप्स के निर्णय अन्तर्गत मैसूर विश्वविद्यालय बनाम सी. डी. गोविंदा राव व अन्य *(1),* महाबीर प्रसाद शर्मा बनाम प्रफुल्ल चंद्र घोष

और अन्य *(2)* और माही चंद्र बोरा बनाम सचिव, स्थानीय स्वशासन, असम राज्य और अन्य (3) का उल्लेख किया है।

(22) इन मामलों में निर्धारित प्रस्तावों के साथ कोई विवाद नहीं है।क्वो-वारंट की रिट की प्रकृति ही सर्वजन को सार्वजनिक पद हड़पने वाले से बचाने के लिए है।

(1) ए. आई. आर 1965 एससी 491
(2) ए. आई. आर1969 कलकत्ता 198
(3) ए. आई. आर 1952 असम 119

हालाँकि, इसे जारी करने से पहले, याचिकाकर्ता के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि नियुक्ति एक सार्वजनिक कार्यालय में है।ऐसी नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं की गई है और नियुक्त व्यक्ति पात्र नहीं है या नियुक्ति कानून के अनुरूप नहीं है।यह केवल तभी होता है जब ये शर्तें पूरी हो जाती हैं कि अदालत यथास्थिति-वारंट जारी करके पदधारी को पद से बाहर कर देती है।वर्तमान मामले में प्रो.गांगुली को जाहिर तौर पर संस्थान द्वारा नियुक्त किया गया है।निर्विवाद रूप से, नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाती है।यह नहीं दिखाया गया है कि प्रो.गांगुली निर्देशक के रूप में कार्य करने के योग्य नहीं हैं।इसके अलावा, यह भी स्थापित नहीं किया गया है कि नियुक्ति नियम 7 की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।

(23) तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हमें संस्थान द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है।

(24) श्री मित्तल ने बताया कि अदालत ने शुरू में प्रो.गांगुली ने निदेशक के पद का कार्यभार संभाला।इसके बाद, प्रतिवादीगण ने तेजी से काम किया।वह बताते हैं कि नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की तुरंत बैठक हुई थी।अब यदि अदालत हस्तक्षेप करने से इनकार करती है, तो प्रतिवादीगण को पद भरने में लंबा समय लग सकता है।

(25) श्री नेहरा ने हमारे सामने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रो.गांगुली ने 13 दिसंबर, 1999 को अदालत द्वारा अंतरिम रोक हटाने के बाद ही पदभार संभाला था।उन्होंने आगे कहा है कि विशेष चयन समिति की बैठक हो रही है और नियुक्ति बिना किसी टालने योग्य देरी के की जाएगी।

(26) इस वचन को ध्यान में रखते हुए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियमित नियुक्ति जल्द से जल्द की जाएगी।

(27) कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है।

(28) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, शुरुआत में पूछे गए दो प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक में दिया जाता है।यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रो.एन के गांगुली कार्यवाहक निदेशक के पद को हड़पने वाले नहीं है।यह भी अभिनिर्धारित किया जाता है कि उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया है।उनकी नियुक्ति नियम 7 के अनुरूप है।इसलिए, वह यथास्थिति-वारंट के एक रिट के जारी होने से निष्कासित होने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

(29) नतीजतन, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। हालाँकि, इन परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

जे एस टी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा चांद,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,
गुरूग्राम, हरियाणा

24140 एच. सी.-सरकार। प्रेस, यू. टी., सीएच. डी.